(केदारनाथ अग्रवाल की कविता)

देश की छाती दरकते देखता हूं।
थान खद्दर के लपेटे स्वार्थियों को,
पेट–पूजा की कमाई में जुता मैं देखता हूं!
सत्य के जारज सुतों को,
लंदनी गौरांग प्रभु की,
लीक चलते देखता हूं।
डॉलरी साम्राज्यवादी मौत–घर में,
आंख मूंदे डांस करते देखता हूं

देश की छाती दरकते देखता हूं
मैं अहिंसा के निहत्थे हाथियों को,
पीठ पर बम बोझ लादे देखता हूं।
देव कुल के किन्नरों को,
मंत्रियों का साज साजे,
देश की जन–शक्तियों का,
खून पीते देखता हूं,
क्रांति गाते देखता हूं।।

देश की छाती दरकते देखता हूं!
राजनीतिक धर्मराजों को जुएं में,
द्रोपदी को हारते मैं देखता हूं!
ज्ञान के सब सूरजों को,
अर्थ के पैशाचिकों से,
रोशनी को मांगते मैं देखता हूं!
योजनाओं के शिखंडी सूरमों को,
तेग अपनी तोड़ते मैं देखता हूं!!

देश की छाती दरकते देखता हूं
खाद्य मंत्री को हमेशा शूल बोते देखता हूं
भुखमरी को जन्म देते,
वन–महोत्सव को मनाते देखता हूं!
लौह–नर के वृद्ध वपु से,
दण्ड के दानव निकलते देखता हूं!
व्यक्ति की स्वाधीनता पर गाज गिरते देखता हूं!
देश के अभिनन्युयों को कैद होते देखता हूं!!
देश की छाती दरकते देखता हूं!
मुक्त लहरों की प्रगति पर,
जन–सुरक्षा के बहाने,
रोक लगाते देखता हूं!
चीन की दीवार उठते देखता हूं!
क्रांतिकारी लेखनी को,
जेल जाते देखता हूं!
लपलपाती आग के भी,
ओंठ सिलते देखता हूं!!

देश की छाती दरकते देखता हूं।
राष्ट्र–जल में कागजी,
छवि–यान बहता देखता हूं,
तीर पर मल्लाह बैठे और हंसते देखता हूं!
योजनाओं के फरिश्तों को गगन से भूमि आते,
और गोबर चोंथ पर सानंद बैठे,
मौन–मन बंशी बजाते, गीत गाते,
मृग मरीची कामिनी से
प्यार करते देखता हूं!
शून्य शब्दों के हवाई फैर करते देखता हूं!!
देश की छाती दरकते देखता हूं

बूचड़ों के न्याय–घर में,
लोकशाही के करोड़ों राम–सीता,
मूक पशुओं की तरह बलिदान
होते देखता हूं!
वीर तेलंगानवों पर मृत्यु के चाबुक
चटकते देखता हूं!
क्रांति की कल्लोलिनी पर घात होते
देखता हूं!
वीर माता के हृदय के शक्ति–पय को
शून्य में रोते विलपते देखता हूं!!

देश की छाती दरकते देखता हूं!
नामधारी त्यागियों को,
मैं धुएं के वस्त्र पहने,
मृत्यु का घंटा बजाते देखता हूं!
स्वर्ण मुद्रा की चढ़ौती भेंट लेते,
राजगुरुओं को,
मुनाफाखोर को आशीष देते,
सौ तरह के कमकरों को दुष्ट कह कर,
शाप देते प्राण लेते देखता हूं!!

देश की छाती दरकते देखता हूं।
कौंसिलों में कठपुतलियों को भटकते,
राजनीतिक चाल चलते,
रेत के कानून के रस्में बनाते देखता हूं!
वायुयानों की उड़ानों
की तरह तकरीर करते,
झूठ का लम्बा बड़ा इतिहास गढ़ते,
गोखुरों से सिंधु भरते,
देश–द्रोही रावणों को
राम भजते देखता हूं!!

देश की छाती दरकते देखता हूं
नाश के वैतालिकों को
संविधानी शासनालय को सभा में
दंड की डौड़ी बजाते देखता हूं।
कंस की प्रतिमूर्तियों को,
मुन्ड मालाएं बनाते देखता हूं।
काल भैरव के सहोदर भाइयों को,
रक्त की धारा बहाते देखता हूं!!

देश की छाती दरकते देखता हूं।
व्यास मुनि को धूप में रिक्शा चलाते,
भीम, अर्जुन को गधे का
बोझ ढोते देखता हूं!
सत्य के हरिचंद को अन्याय–घर में,
झूठ की देते गवाही देखता हूं!
द्रोपदी को और शैव्या को, शची को,
रूप की दूकान खोले,
लाज को दो–दो टके
में बेचते मैं देखता हूं!!

देश की छाती दरकते देखता हूं।
मैं बहुत उत्तप्त होकर
भीम के बल और अर्जुन की प्रतिज्ञा से
ललक कर,
क्रांतिकारी की शहादत का हथौड़ा हाथ
लेकर,
श्रृंखलाएं तोड़ता हूं
जिन्दगी को मुक्त करता हूं नरक से!!

पेज 1 का शेष भाग

मोदी का उभार कांग्रेस के लिए

तथाकथित आर्थिक वृद्धि का उनका मॉडल उनके अपने आंकड़ों के दलदल से ही नहीं निकल पा रहा। बेरोजगारी और असुरक्षा को लेकर सामाजिक ढांचा पूरी तरह चरमराने लगा है। राहुल गाँधी का अपना चेहरा भी लोगों में विश्वास नहीं पैदा कर पा रहा। यहाँ तक कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हालिया जीत भी कांग्रेस के खाते में कम और भाजपा से असंतोष के खाते में ज़्यादा मानी जा रही हैं।

सवाल है कि इन समीकरणों से क्या गणित निकलता है? यानि आगामी चुनाव के बाद पीएम कौन? मोदी, राहुल गाँधी, नितिश कुमार या कोई और? क्या मोदी की भाजपाई हवा, राष्ट्रीय आंधी में बदल पायेगी? क्या एक बार फ़िर लोग मजबूरी में कांग्रेस को वापिस सत्ता में लाना चाहेंगे? क्या नितीश कुमार अपनी ज़मीन को फ़िर से मजबूत कर पाएंगे ताकि बीच में मौके का फ़ायदा उठाकर आम-सहमति से कुर्सी की दावेदारी कर सकें?

यदि चुनाव में किसी पक्ष का बहुमत नहीं आया तो अधर से नितिश कुमार क्या, कई और दावेदार भी निकल कर सामने आ सकते हैं। मोदी के दबदबे वाली भाजपा नितीश कुमार को समर्थन देगी, इसमें संदेह है। इसी तरह कांग्रेस का समर्थन लेकर बिहार में अकेले लड़ जाने का ख़तरा भी नितीश के लिए उठाना आसान नहीं होगा। फ़िर इसकी भी क्या गारंटी है कि कांग्रेस का समर्थन लगातार मिलता रहेगा। साथ ही राज्यों में ताकतवर तमाम कांग्रेस विरोधी खेमे उस हालत में कांग्रेसी कठपुतली बन नितीश कुमार को समर्थन क्यों देंगे? कांग्रेस (राहुल गाँधी) के पास बेशक लोकप्रिय अपील नहीं है पर सत्ता में होने के नाते वे तरह-तरह की रणनीतियाँ अवश्य इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जैसी लोकलुभावन योजनाओं से पैसा ग्रामीण क्षेत्रों में सीधे पहुंचाया गया, रीयल एस्टेट, शेयर बाज़ार जैसे क्षेत्रों को काले धन की गर्मी से रोशन रखा गया, तमाम घोटाले तब तक दबे हुए थे, और अभी मोदी या नितीश कुमार जैसे नए विकल्प भी नहीं उभरे थे। अब नई रणनीतियां लाने की तैयारी देखी जा सकती है।

ऐसे में खाद्य सुरक्षा एवं सब्सिडी का सीधा खाते में भुगतान, दो ऐसे मंत्र हैं जो कांग्रेस अपने पक्ष में इस्तेमाल करने को व्याकुल नज़र आती है। हो सकता है मनरेगा को और आकर्षक बनाने की कवायद भी की जाए। इन मंत्रों की सिद्धि को लेकर कांग्रेस का मानना यह है कि वह जितना अधिक पैसा आम वोटर की जेब में सीधा डाल पाएगी, उतने ज़्यादा वोट उसकी झोली में गिरेंगे। यदि वह अकेली बड़ी पार्टी के रूप में आई तो जोड़-तोड़ करके सरकार बनाने का विकल्प उसके पास होगा ही।

पर कांग्रेस (राहुल गाँधी) का सबसे बड़ा मददगार स्वयं भाजपा का मोदी चेहरा ही सिद्ध होगा। कैसे? मोदी के चेहरा बनते ही भाजपा के तमाम पारम्परिक वोट उसकी झोली में आने सुनिश्चित हो जाएंगे। साथ ही वह तबका भी भाजपा की ओर आएगा जो मोदी की कार्यशैली में अपने मुनाफ़े की बेरोक-टोक गारंटी देखता है। पर इसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीखी होगी। तमाम अल्पसंख्यक वोट जो अन्यथा विभिन्न पार्टियों में बंटते अब एक साथ कांग्रेस की झोली में इस डर से पहुंच जाएंगे कि कहीं मोदी न आ जाए। इसी प्रकार दलित तबके भी मोदी विरोधी राजनीतिक खेमों को मजबूत करने का काम अंजाम देंगे। ऐसे में यदि नगदी सीधे वोटर तक पहुंचाने की रणनीति चल पड़ी तो मोदी की दाल नहीं गल पाएगी।

चुनाव के बाद स्वयं भाजपा के अंदर मोदी का समर्थन इस बात पर निर्भर करेगा कि भाजपा को कुल सीटें कितनी मिलती हैं। यदि सीटें कम रहीं तो आडवाणी समेत तमाम अन्य दावेदार मोदी को दरकिनार करने में कोई कसर न उठा रखेंगे। कांग्रेस की एक अंतिम रणनीति यह भी बन सकती है कि मोदी को गुजरात २००२ नरसंहार में दोषी बनाकर चुनाव परिदृश्य से ही हटा दिया जाए, उपरोक्त नरसंहार में मोदी की भूमिका जगजाहिर है। परन्तु पैसे, पद और कार्पोरेट समर्थन की बदौलत वह उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाई विशेष जांच टीम के द्वारा छोड़ दिया गया है। यूं तो पूर्व सीबीआई निदेशक विजय राघवन की अध्यक्षता वाली टीम ने जैसी लीपा-पोती वाली रिपोर्ट दी है, उसे हास्यास्पद ही कहा जाएगी। पर सवाल है कि क्या कांग्रेस की सीबीआई में इतना दम है कि राघवन द्वारा मोदी के पक्ष में किए धरे पर पानी फ़ेर सके। यानी तख्त की लड़ाई में तख्ता भी अपनी भूमिका निभा सकता है।

अगर वास्तव में मोदी पीएम बन गया तो क्या होगा? देश का क्या होगा, भाजपाई नेताओं का क्या होगा, स्वयं मोदी का क्या होगा? ज़ाहिर है देश में फ़ासीवाद का एक दौर आएगा जो आम जनता को विभाजित एवं कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। क्या मोदी का हश्र वैसा ही नहीं होगा जैसा इतिहास में फ़ासीवादी नेताओं का हुआ है? हिटलर, मुसोलिनी, गद्दाफी, पिनोशे जैसे उदाहरण सामने हैं।

असल चार सौ बीस है आईपीएल

जो श्रीनिवासन के विश्वासपात्र आईपीएस अधिकारी रवि सवानी द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस दस्ते का कोई न कोई सदस्य हर आईपीएल मैच में निगरानी के लिए तैनात होता था। जब खुलेआम सटोरियों एवं खिलाड़ियों की होटलबाज़ी चल रही हो तो इस दस्ते की नज़र से कैसे बची रह सकी होगी? ज़ाहिर है यह दस्ता बोर्ड और आईपीएल की 'इज्जत' ढकने का काम अंजाम दे रहा था, न कि उनकी बदमाशियों को पकड़ने का। ज़ाहिर है जिन आकाओं से उन्हें लम्बी चौड़ी पगार और सुख-सुविधाएं मिल रही हों उनके मीन-मेख वे क्यों निकालेंगे?

बोर्ड या आईपीएल की तरफ़ से एक बार भी इस दस्ते से यह नहीं पूछा गया कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर चलने वाले सट्टा-कारोबार की कोई रिपोर्ट क्यों नहीं की? और यदि दस्ते ने कोई रिपोर्ट की थी तो बोर्ड या आईपीएल की तरफ़ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब सटोरियों ने मालिकों और खिलाड़ियों को खरीद लिया तो क्या दस्ते के सदस्यों पर उन्होंने डोरे नहीं डाले होंगे? क्या इस बाबत जांच नहीं होनी चाहिए?

कमाल तो यह भी है कि जहाँ दिल्ली पुलिस ने मकोका लगा दिया वहां उसी प्रकरण से संबंधित मुंबई पुलिस के केस में मकोका लगाना जरूरी नहीं समझा गया। क्या इसलिए कि इसमें श्रीनिवासन का दामाद और चेन्नई सुपर किंग का मालिक भइयप्पन शामिल हैं। मकोका न लगाने से भइयप्पन और उसके बिचौलिए बिंदू दारासिंह की जमानत हो गई है। यदि प्रकरण के तार वास्तव में दाऊद इब्राहिम से जुड़े हैं तो मुंबई पुलिस द्वारा मकोका न लगाने को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि केन्द्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे स्वयं महाराष्ट्र से आते हैं। दिल्ली पुलिस सीधे केन्द्रीय गृहमंत्रालय के अधीन होती है और शिंदे के लिए यह जानना मुश्किल नहीं है कि उनके द्वारा मकोका लगाने का आधार क्या है?

दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस में कौन सही कानून लगा रहा है और कौन कोताही कर रहा है, क्या यह जानना शिंदे के लिए जरूरी नहीं है? विशेषकर तब जब षड्यंत्र में दाऊद इब्राहिम का नाम आ रहा हो। क्या बिना श्रीनिवासन, राजीव शुक्ला और रवि सवानी से पूछताछ किए पूरा षडयंत्र सामने आ पाएगा?

सट्टेबाजी का खेल और पुलिसिया घालमेल

जानकार बताते हैं कि छापा मारने वाले एसीपी हितेष ने तो एफआईआर दर्ज करते वक्त भा.द.सं. लगाने के लिए बहुत हाथ पांव मारे थे, परन्तु मौके पर पहुंचे डीसीपी देवेन्द्र सिंह यादव ने सीपी से गुट-गुट करके केवल जुआ एक्ट ही लगने दिया। इस पर नाराज़गी प्रकट करते हुए एसीपी ने यह भी कहा बताते हैं कि यदि जुआ एक्ट ही लगाना था तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। सीपी से हुई गुट-गुट का ही परिणाम था कि गिरफ्तार सभी आरोपियों को रात हवालात में बंद न कर के बाहर ही सुलाया गया था। जाहिर है कि यह गुट-गुट कोई मुफ्त में तो हो नहीं सकती। इसके लिए अच्छा खासा लेन-देन संभावित है।

सूत्रों की मानें तो 2 लाख तो उस थानेदार ने ही ले लिए थे जिसने इस सौदे में बिचौलियों की भूमिका निभाई थी। इस छापे के दौरान आयातित शराब की जो बोतलें पकड़ी गई थीं वे भी खुर्द-बुर्द कर दी गईं।

मामला यहीं खत्म नहीं हो गया। चर्चा जोरों पर है कि फ़ोन टेप के आधार पर कई और पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिर सकती है। कुछ दिन पहले तक यहाँ तैनात रह चुके कुछ एसीपी व डीसीपी स्तर के अधिकारियों के नाम भी इस लिस्ट में हैं। कहा जाता है कि इनके बारे में लिखित रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय पंचकूला भेज दी गई है। इसी संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण पहलू और पैदा होता है। टेलीफ़ोन पर बतियाने वालों को तो निलम्बित किया जा रहा है और संयुक्त पुलिस आयुक्त संजय कुमार के शहर के एक सबसे बड़े सटोरिए हरीश पकोड़ा से एक होटल में नियमित रूप से मिलने पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? जानकार तो यहां तक भी कहते हैं कि इनके रीडर हुकम सिंह का नाम भी फ़ोन टेप वालों की लिस्ट में था, जिसे बाद में काट दिया गया। अन्य महत्त्वपूर्ण सवाल बनता है कि थाना सेंट्रल वाले केस में सतही एफआईआर दर्ज करने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या उस मामले में भी पुलिसकर्मियों की मिलीभगत नहीं रही होगी? क्या शामिल पुलिसकर्मियों के नाम जानने की कोशिश की गई? दोनों मामलों में आईटी एक्ट का न लगाया जाना भी पुलिस की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। यह उनकी पेशेवराना नालायकी का सबूत भी है। सौदा, नालायकी या दोनों?